फरीदाबाद
मजदूर समाचार
राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

'मजदूर समाचार' की कुछ सामग्री अंग्रेजी में इन्टरनेट पर है। देखें—
< http://faridabad majdoorsamachar.blogspot.in >

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी, आटोपिन झुग्गी,एन.आई.टी. फरीदाबाद — 121001

नई सीरीज नम्बर 308 1/— *फरवरी* 2014

फोन किया, पोस्ट कार्ड डाले

दिल्ली सरकार के श्रम आयुक्त को फोन किया। मजदूर बोल रहा हूँ बताने पर थोड़ी देर हाँ-हाँ कर साहब ने फोन काट दिया।

मैंने 10 जनवरी को छुट्टी की थी। उस दिन मैं दिल्ली सचिवालय भी गया। मुख्य मन्त्री के नाम पत्र रिसीव करने को अधिकारी को दिया तो उसने पत्र पढ़ा और फिर बोला कि 120 मजदूरों के हस्ताक्षर चाहियें तब पत्र की पावती देंगे। मैंने दस्तखत करने पर नौकरी से निकाल दिये जाने की बात कही तो अधिकारी ने कहा कि एक का नाम दो। हस्ताक्षर कर दिया तो अधिकारी बोला कि पूरा पता भी लिखो। पते पर एतराज करते हुये मैंने गुण्डागर्दी की बात बताई तो अधिकारी बोला कि सरकारी काम ऐसे नहीं होता। तब मैंने मुख्य मन्त्री के पास जाने की बात की तो अधिकारी झल्ला गया और बोला कि बात झूठ हो सकती है इसलिये पता जरूरी है ताकि जाँच कर सरकार आपको बताये। मैंने कहा कि मुझे नहीं, कम्पनी डायरेक्टर को बताओ..... पर अधिकारी ने पत्र रिसीव नहीं किया।

दुबारा फोन किया। साहब बोले कि मेरी बात सुन ली है। मेरे यह कहने पर कि आपने कम्पनी का प्लॉट नम्बर तो पूछा ही नहीं, उन्होंने कहा बताइये। मैंने फैक्ट्री का पूरा पता बताया। तब साहब बोले कि लिखित में दो तब कार्रवाई करूँगा। ऐसे में नौकरी को खतरा बताया तो साहब बोले कि कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है। नाम नहीं बताना चाहता कहा तो साहब बोले कि एक बार मिल लो और उप श्रमायुक्त से भी मिलो। तब मैंने उन्हें पोस्ट कार्ड द्वारा शिकायत की बात बताई। श्रम विभाग से जाँचवाले फैक्ट्री आते हैं, कुछ हल्ला होता है, पर फैक्ट्री में दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता। तब श्रमायुक्त बोले कि ठीक है, कार्रवाई करूँगा।

कई प्रयास के बाद पुष्प विहार में बैठते उप श्रमायुक्त ने फोन उठाया। उन्हें अपनी बात बताई तो बोले कि लिख कर दो। नाम देने पर दिक्कतें बताई तो साहब बोले कि भाई, सरकारी काम ऐसे नहीं होता। उन्हें पोस्ट कार्ड पर भेजी लिखित शिकायत के बारे में बताया तो साहब बोले कि यहाँ मत आना, सारा काम फोन से ही करवा लो..... और फोन काट दिया।

दिल्ली मुख्य मन्त्री, श्रम मन्त्री भारत सरकार, दिल्ली श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त को हर हफ्ते पोस्ट कार्ड डालना शुरू किया। इन में मोडेस्ट प्रिन्टर्स, सी-52 तथा सी-53 डी डी ए शेड, ओखला फेज-1, दिल्ली में काम करते 120 मजदूरों में अधिकतर को न्यूनतम वेतन नहीं दिये जाने की बात थी।

आसानी से उठाये इन छोटे-छोटे कदमों का असर दिखा है। श्रम विभाग वाले दूसरे-तीसरे दिन फैक्ट्री आने लगे हैं। तंग आये डायरेक्टर ने मैनेजर से कहा है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन देना ही ठीक रहेगा। पता 7 फरवरी को तनखा के समय लगेगा।

दिल्ली सरकार ने एन्टी-करप्शन हैल्पलाइन नम्बर 1031 दी है। इस नम्बर पर फोन किया तो एक महिला ने स्वागत किया। यह बता कर कि मैं ओखला में एक फैक्ट्री में मजदूर हूँ, मैंने कहा, ''मैम, आप से एक जानकारी चाहता हूँ।'' उनके ''बोलो'' कहने पर मैंने बताया कि जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ वहाँ दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं देते, और पूछा : ''मैम, क्या यह भ्रष्टाचार है ?'' मैम बोली कि हाँ, यह भ्रष्टाचार है। तब मैंने उन से इस पर कार्रवाई करने को कहा। तब मैम बोली, ''एन्टी-करप्शन हैल्पलाइन में यह सुविधा नहीं है। अगर आप से कोई रिश्वत माँगता है तो यह हैल्पलाइन उसके लिये है।'' मैंने और बात की तो मैम बोली कि एन्टी-करप्शन हैल्पलाइन रिश्वत के मामलों के लिये ही है। मैम ने कहा कि वो मेरी बात समझती हैं पर मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दिये जाने जैसे भ्रष्टाचार के मामले में वे कुछ नहीं कर सकती।

औद्योगिक क्षेत्र में हाथ से लिखे, दीवारों पे चिपके पर्चे से :

देंगे कि नहीं देंगे ?

मिलेगा कि नहीं मिलेगा ?

यह बातें बहुत हो गई।

पूर्वज्ञान : वो जो भविष्य की सिलवटें वर्तमान की तहों में ला छोड़ता है।

साँझा : वो जो हम सब के बीच है, हवा जिसमें हम साँस लेते हैं, नुक्कड़, सभा-स्थल, राह।

आधार : ये शहर, ये पृथ्वी, ये समय, अभी, यहाँ।

प्रतिरूप : वो जो नया है, जो पूर्वानुमान लगाता है, जिक्र और अभ्यास करता है, आधार तैयार करता है।

उपजाऊ : वो जो खुद में हो रहे घाटे को पार कर अपनी बहुतायत से पोषण करता है।

अग्नि-बाण : वो जो हमें दूर ले जाये, हमारे अपने चुने ग्रहपथों पर।

सामुहिक बेहोशी उत्पादन ठप्प कर देती है

कम्पूचिया-कम्बोडिया-खमेर राज्य की सीमायें वियतनाम राज्य से मिलती हैं और 35-45 वर्ष पहले यह क्षेत्र मण्डी-मुद्रा के विस्तार से जुड़ी खून-खराबों की रिपोर्टों से विश्व घटना उद्योग की सुर्खियों में आता रहता था। अब यह क्षेत्र सैनिक-रूपी सरकारों और मजदूरों के बीच टकरावों का अखाड़ा बना है।

आज कम्बोडिया राज्य में 600 फैक्ट्रियों में चार लाख पचास हजार मजदूर वस्त्रों की सिलाई करते हैं। सरकार को निर्यात से होती आमदनी का अस्सी प्रतिशत हिस्सा सिले-सिलाये कपड़ों से मिलता है। इसलिये गारमेन्ट वरकरों के मुखर सामुहिक कदमों के समय सरकार कठोर और हिंसक हो जाती है। सितम्बर 2010 में दो लाख कपड़ा मजदूर सड़कों पर निकले और तीन दिन उत्पादन ठप्प किया तब सरकार ने पुलिस व सेना के हिंसक करमों से मजदूरों पर नियन्त्रण....... ''नियन्त्रण'' स्थापित किया।

मजदूरों को नियन्त्रण में रखने के लिये 400 यूनियनें भी हैं जिनमें से 394 यूनियनें कम्पनियों की अथवा सरकार की हैं। सितम्बर 2010 की सरकारी हिंसा के बाद मजदूरों के बीच लोक-जन देवी-देवता सक्रिय हुये। कॉमपाँग प्रान्त में अन्फुल गारमेन्ट्स फैक्ट्री में 250 मजदूर बेहोश हो गये, अस्पताल ले जाये गये, उत्पादन ठप्प हो गया। दो दिन बाद फैक्ट्री में उत्पादन पुनः आरम्भ हुआ और फिर सामुहिक बेहोशी। लोक-जन देवी-देवता का एक मजदूर में प्रवेश और देखते-देखते सैंकड़ों मजदूर बेहोश! एक फैक्ट्री में दर्जनों मजदूर अचानक बेहोश हो गये और शक्ति से सराबोर एक महिला मजदूर ने सरकारी यूनियन के प्रधान को खूब घूँसे मारे, उस पर गालियों की बौछार की। अगस्त 2012 में खेल सामग्री निर्माण फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर ने मजदूरों को कुछ फुरसत देने से इनकार कर दिया तब दो दिन बाद लोक-जन देवी-देवता प्रकट और कई दर्जन मजदूर बेहोश हो गये, अस्पताल ले जाने पड़े, सुपरवाइजर घुटनों के बल बैठ गया, आदेश का पालन कर माह में चार दिन फुरसत तो दी ही, संग-संग मजदूरों को भोज भी करवाया। सामुहिक बेहोशी उत्पादन ठप्प कर देती है। सामुहिक बेहोशी की बढती घटनाओं ने सरकार, फैक्ट्री मैनेजमेन्टों, एच एण्ड एम-गैप-वॉल मार्ट-अडिडास-लेवी स्ट्रॉस जैसी वैश्विक व्यापारिक कम्पनियों को चिन्ताग्रस्त किया है। इसलिये मजदूरों की तन-मन की इन उड़ानों का विद्वान अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञानी ढेरों कान्फ्रेन्सें कर रहे हैं.....

इधर 2 व 3 जनवरी को फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप्प कर मजदूर फिर झुण्डों में सड़कों पर निकले। सेना और मिलिट्री पुलिस ने 3 जनवरी 2014 को मजदूरों पर गोलीबारी की — पाँच मजदूरों की मृत्यु और दर्जनों घायल।

लोक-जन देवी-देवता उत्तरी यूरोप में दो सौ वर्ष पूर्व मजदूरों के बीच सक्रिय थे। दक्षिणी अमरीकी महाद्वीप में कोलम्बिया में 1970 में....... एशिया में मलेशिया में 1970 के दशक में इलेक्ट्रोनिक्स फैक्ट्रियों में लोक-जन देवी-देवता प्रकट होते और चीखती-चिल्लाती महिला मजदूर सुपरवाइजरों पर पिल पड़ती। मजदूरों की यह रचनात्मकता ही है कि उन्होंने मण्डी-मुद्रा के वाहक वाहन विज्ञान को भी लोक-जन देवी-देवता बना डाला : अमरीका में रसायनिक गैस की चर्चा, मजदूरों के बेहोश होने का सिलसिला, फैक्ट्री खाली करवाना, उत्पादन बन्द, विशेषज्ञों की सूक्ष्म जाँच का परिणाम शून्य।

तन, मन, मस्तिष्क को बेलगाम छोड़ने का समय है। यथास्थिति को काँपने दें। रचना, सृजना, creativity की कोई सीमा नहीं होती।

(जानकारी जूलिया वालेस, सम्पादक 'दी कम्बोडियन डेली' के न्यू यॉर्क टाइम्स में 17.1.2014 के लेख "Workers of the World, Faint !", 'मजदूर एकता लहर' के 16-31 जनवरी 2014 अंक, और न्यूज एण्ड लैटर्स के जनवरी-फरवरी 2014 अंक से ली हैं।)

लाइन पर हँस ..... (पेज तीन का शेष)

अल्फा लावेल की पोलैण्ड, फ्रान्स, चीन, अमरीका, जापान, डेनमार्क, स्वीडन आदि में फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ कम्पनी का पहले वाला मैनेजिंग डायरेक्टर अमरीका से था और अब वाला जापान से है। यहाँ कम्पनी की थाणे, सतारा, सारोला में फैक्ट्रियाँ हैं और शिर्वल में नई बड़ी फैक्ट्री बन रही है। मित्रों के जरिये हम ने अपनी बातें फैलाई हैं। कम्पनी की इन्टरनेट साइट पर सवाल पूछे जाने लगे तो आरम्भ में ''देखेंगे'' कहा गया और फिर उस साइट को ही कम्पनी ने ब्लॉक कर दिया। कम्पनी का मुख्यालय स्वीडन में है और वहाँ के साथियों ने इन्टरनेट पर नई साइट बनाई है जिस पर कम्पनी को परेशान करने वाले सवाल दुनिया-भर से पूछे जाने लगे हैं। कम्पनी के दिल्ली कार्यालय पर मित्र प्रदर्शन कर चुके हैं। हम भी जर्मनी में, स्वीडन में, इंग्लैण्ड आदि-आदि में मित्रों की, साथियों की सँख्या बढा रहे हैं।

टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, महिन्द्रा, फॉक्स वैगन, मर्सीडीज बैन्ज, फोर्स मोटर, एस के एफ, अल्फा लावेल, भारत फोर्ज आदि-आदि फैक्ट्रियाँ पुणे को वाहन उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र बनाती हैं। पुणे में संग-संग एक बड़ा आई टी-बी पो ओ क्षेत्र भी है। इधर 21-22-23 जनवरी को पुणे में कुछ मजदूरों से हुई बातचीत के अंश ऊपर दिये हैं।

फोन करें, पोस्ट कार्ड डालें

दिल्ली : 1. मुख्य मन्त्री, थर्ड लेवल, ए विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्र प्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली— 110002
फोन नं. 23392020, 23392030

2. श्रम आयुक्त दिल्ली सरकार, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली—110054 फोन नं. 23951115, 23962823 (फैक्स)

हरियाणा : 1. मुख्य मन्त्री, चौथी मंजिल, हरियाणा सचिवालय, चण्डीगढ
फोन नं. 0172-2749396 (ऑफिस), 0172-2740877 (निवास)

2. श्रम मन्त्री, छठी मंजिल, हरियाणा सचिवालय, चण्डीगढ
फोन नं. 0172-2740145

3. श्रम आयुक्त, 30 बेज बिल्डिंग, पहली मंजिल, सैक्टर-17, चण्डीगढ फोन नं. 0172-2701373, 2701266 (फैक्स)

लाइन पर हँस रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे

— आप लाइन पर हँस रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। ......

— आप मनमर्जी से लाइन पर अपना स्थान बदल रहे थे।....

— आप जानबूझ कर लाइन को रोक रहे थे।......

— आप ने कम्पनी के अधिकारी का आदेश नहीं माना। यह कम्पनी और यूनियन के बीच 21 मई 2010 को हुये बाध्यकारी समझौते का उल्लंघन है। इसलिये कम्पनी के प्रमाणित स्थाई आदेशों की धारा 31 (i, ii, iii, iv....x....xx....xxx....xxxiv...) के तहत यह गम्भीर दुराचरण है। इसलिये 72 घण्टे में स्पष्ट करें कि क्यों न आपके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये।

मजदूरों के उत्तर पर कम्पनी का निर्णय : उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। ऐसे में हमारे द्वारा आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाना न्यायसंगत होता। लेकिन आपको स्वयं को सुधारने के लिये एक अवसर देते हुये इस बार नरम रुख का निर्णय लिया है। आपको निलम्बित किया जाता है......... 4 दिन-6 दिन-12 दिन बिना वेतन के, घरेलू जाँच की अवधि के लिये।

यह ***बजाज ऑटो*** की चाकण (पुणे, महाराष्ट्र) फैक्ट्री में स्थाई मजदूरों और मैनेजमेन्ट के बीच जारी खींचातान है।

बजाज ऑटो की चाकण फैक्ट्री में 925 स्थाई मजदूरों, पाँच ठेकेदार कम्पनियों के जरिये रखे 900 मजदूरों, कमाओ और सीखो वाले 600 लड़कों, और आई टी आई-डिप्लोमा वाले 500 ट्रेनी की 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट थी और 12 घण्टे के बाद 4 घण्टे नियमित-सा रोकते थे। कम्पनी की आकुर्डी, पुणे फैक्ट्री की मान्यताप्राप्त यूनियन ने 2010 में चाकण फैक्ट्री के स्थाई मजदूरों को सदस्य बनाया तब से स्थाई मजदूर ए, बी, जनरल शिफ्ट में 9 घण्टे 15 मिनट और सी शिफ्ट में 8 घण्टे 25 मिनट ही फैक्ट्री में रहते हैं। लेकिन ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों की 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट जारी हैं, इन 900 में 100 मजदूरों की ही ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं, कम्पनी रिकार्ड में तनखा 8-9 हजार पर ठेकेदार को 5-6 हजार देते हैं और मजदूर के हाथ 8 घण्टे के 170-180 रुपये ही आते हैं। कोर्ट केसों के कारण अप्रैल 2013 के बाद कमाओ और सीखो वाले लड़कों की संख्या 600 से 200 हो गई है।

चाकण फैक्ट्री में सब स्थाई मजदूर आई टी आई अथवा डिप्लोमा किये युवा मजदूर हैं। उत्पादन में जोते डिप्लोमा वालों को कम्पनी लाइन इंजीनियर कहती है। बजाज ऑटो चाकण फैक्ट्री मैनेजमेन्ट और यूनियन के बीच 21 मई 2010 को हुआ समझौता 9 वर्ष के लिये है। इस में प्रबन्धन के ज्ञानियों की शायद ही कोई बात छोड़ी गई है जिसे मजदूरों के लिये बाध्यकारी नहीं बनाया गया हो। प्रबन्धन विद्वानों की कल्पना ने खूब उड़ानें भरी हैं और वे सब इस 9 वर्षीय समझौते में हैं।

बजाज ऑटो चाकण फैक्ट्री के युवा स्थाई मजदूरों ने व्यवहार और विचार में बाध्यकारी समझौते को कागज के टुकड़े के तौर पर लिया है। ऐसे में मजदूरों को नियन्त्रण में रखने के लिये निलम्बन का अस्त्र मैनेजमेन्ट लगातार चला रही है। सन् 2012 के निलम्बनों के बाद जनवरी 2013 से इनकी सँख्या बढ़ती गई। ऐसे में युवा मजदूरों का यूनियन नेताओं पर भारी दबाव कारण लगता है यूनियन निर्देश पर 15 जून से 14 अगस्त 2013 तक 50 दिन चाकण फैक्ट्री में उत्पादन बन्द रहना।

21 जनवरी 2014 तक बजाज ऑटो चाकण फैक्ट्री में 200 से ज्यादा स्थाई मजदूर 2 से 12 दिन तक निलम्बित किये जा चुके हैं। घरेलू जाँच के चलते 13 निलम्बित हैं। दो स्थाई मजदूर नौकरी से निकाले जा चुके हैं। इन युवा स्थाई मजदूरों का उत्साह तथा इनकी जानकारियाँ प्रेरित करने वाली हैं। स्थाई मजदूरों, ट्रेनियों, कमाओ और सीखो वाले लड़कों, ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों के बीच जोड़ बनने-बनाने पर खूब कमाल होते दिखते हैं।

✶ पुराने पुणे-मुम्बई राज मार्ग पर दापोड़ी स्थित ***अल्फा लावेल*** फैक्ट्री में 60 स्थाई मजदूर, 250 स्टाफ (आई टी आई किये हैं, मशीनें चलाते हैं), 200 केबिन स्टाफ, और चार ठेकेदार कम्पनियों के जरिये रखे 600 मजदूर भोजन लाइन तथा तेल लाइन के लिये पाइप लाइन, टैंक, हीट एक्सचेन्जर, हीटिंग सिस्टम बनाते थे। मिल्क प्लान्ट का तो पूरा प्लान्ट ही फैक्ट्री में तैयार होता है। फरवरी-मार्च 2013 से बिना सूचना के कम्पनी अचानक ठेकेदारों के जरिये रखे 50-60 मजदूरों को निकालने लगी। वर्षों से वहाँ काम कर रहे हम बचे हुये 402 लोगों ने जून-जुलाई में अन्दर ही अन्दर आपस में विचार करना आरम्भ किया। तभी हमारे बगल की सिम्मन्स मार्शल फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे 40-50 मजदूर एक यूनियन के नेतृत्व में 45 दिन की हड़ताल के बाद परमानेन्ट किये गये। हम उस यूनियन से जुड़े। नेता ने 15 सितम्बर को कम्पनी को माँग-पत्र दिया और समाधान के लिये 15 दिन का समय दिया। कम्पनी ने बात भी नहीं की। ठेकेदारों के जरिये रखे हम 402 मजदूर 1 अक्टूबर को फैक्ट्री से बाहर आ कर गेट पर बैठ गये। दीवाली पर अधनंगे बैठे। अनशन किया। भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिव सेना, रिपब्लिकन पार्टी, मनसे के नेताओं ने गेट पर आ कर गर्मागर्म भाषण दिये। यूनियन नेता की राष्ट्रवादी काँग्रेस के मंत्रियों की रैलियों में हम गये और मन्त्रियों से अपनी बात कही तो वे बोले कि छोटी-छोटी बातें ले कर हमारे पास मत आओ, लोकल नेताओं के पास जाओ। गेट पर बैठे एक महीना हो गया उसके बाद कोई पार्टी नेता हमारे पास नहीं आया। हम ने थोड़ी गर्मी दिखाई तो पुणे पुलिस आयुक्त ने यूनियन नेता और मैनेजमेन्ट की वार्तायें करवाई पर मामला जस का तस रहा। अक्टूबर के बाद नवम्बर भी निकलने को हुआ तब लीडर मामले को लेबर कोर्ट ले गया। फैक्ट्री में ठेकेदारों के लाइसेन्स गार्डन तथा हाउसकीपिंग के लिये ही थे जबकि हम 402 वैल्डर, फिटर, ग्राइन्डर, इलेक्ट्रीशियन, शीट मैटल के काम करते थे। आई टी आई तथा इसी फैक्ट्री में ट्रेनिंग व जॉब के कागज हमारे पास थे। श्रम न्यायालय ने हमें कम्पनी के मजदूर करार दे कर 15 दिसम्बर को ड्युटी पर लेने का आदेश दिया। कम्पनी अपील में गई, तारीखें पड़ रही हैं........ **(बाकी पेज दो पर)**

लहरें खुल गई, बातें खुल गई
चलो-चलो साथी, नावें खुल गई।
— मनहंस कुमार 'नील', लुमला, तवांग, अरुणाचल प्रदेश

मजदूरों के समूह एक से दूसरी फैक्ट्री पहुँचे

✶हरियाणा में 1 जनवरी 2014 से 8100 रुपये न्यूनतम वेतन वाली मुख्य मन्त्री की घोषणा को तीन महीने हो गये थे। फैक्ट्री बस ने 23 जनवरी की सुबह जे सी बी चौक पार किया तभी से दोनों तरफ से ट्रकों-बसों का जाम आरम्भ हो गया और यह 13-14 किलो मीटर तक मिला। बीच की सड़क खाली थी और बस को किसी ने नहीं रोका। राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 2 पर 49 मील पत्थर, पृथला साढे आठ के करीब पहुँचे तब वहाँ 500 से ज्यादा मजदूर सड़क के किनारे 8100 के लिये और कम्पनियों व सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ लम्बा जाम बघौला-पृथला औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री मजदूरों की हलचल के कारण था। राज्य कर्मचारियों की 21, 22, 23 जनवरी की हड़ताल ने फैक्ट्री मजदूरों को प्रोत्साहित किया था पर 21 और 22 जनवरी को सड़क पर जाम नहीं था।

23 जनवरी को मजदूर सड़क के बीच नहीं जमे। बल्कि, मजदूरों के समूह एक से दूसरी फैक्ट्री पहुँचे। शिवानी लॉक्स बन्द, बायो मेडिकल बन्द, हरियाणा वायर बन्द, महिन्द्रा बन्द, वमानी ओवरसीज बन्द, एस के एच बन्द, महारानी पेन्ट्स बन्द, ऑटो इग्निशन बन्द। सुबह साढे नौ के करीब पुलिस की एक जिप्सी वहाँ से निकली। मजदूरों के समूह फैक्ट्रियों के अन्दर साहबों के ऑफिसों में भी गये और उन्हें भी फैक्ट्री से बाहर निकलने को कहा। स्थाई-अस्थाई मजदूर, स्टाफ और साहब लोग ऑटो इग्निशन फैक्ट्री के बाहर खड़े थे जब साढे 10 बजे पुलिस की जिप्सी आई और पुलिसवाले बोले कि अन्दर जाओ, हम देखेंगे। इस पर 850 लोग फैक्ट्री के अन्दर चले गये। पुलिस की गाड़ी के वहाँ से जाते ही 250 मजदूर सवा 11 बजे फिर ऑटो इग्निशन फैक्ट्री के अन्दर पहुँचे और फिर सब लोग फैक्ट्री से बाहर निकले। एक स्थानीय नेता पहुँचा। मैनेजमेन्ट बोली कि लीडर आये हैं, उनकी बात सुन लो। सब लोग फैक्ट्री के अन्दर पार्क में पहुँचे। नेता ने शांति बनाये रखने को कहा और फिर बोला कि मैं मैनेजमेन्ट से बात कर लेता हूँ। मैनेजमेन्ट और नेता की मीटिंग के बाद कम्पनी ने 23 जनवरी की छुट्टी कर दी। क्षेत्र की सब फैक्ट्रियों में 23 जनवरी को उत्पादन बन्द रहा। कोई भी मजदूर 23 जनवरी को गिरफ्तार नहीं हुआ। चर्चा 4 दिन फैक्ट्रियाँ बन्द रखने की थी। अगले दिन सुबह सवेरे से ही भारी पुलिस बल क्षेत्र में था। फैक्ट्री गेट पर 24 जनवरी को बस पहुँची तब वहाँ 4 जिप्सी और 1 बस पुलिस मौजूद थी। भोजन अवकाश के समय भी पुलिस उपस्थित थी। एस.एस. पी. पलवल स्वंय फैक्ट्रियों में मैनेजमेन्टों को आश्वस्त करने पहुँचा था। मजदूरों ने पँगा लेना ठीक नहीं समझा। फैक्ट्रियाँ चली।

फरीदाबाद इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने राज्य सरकार से शिकायत की। उपद्रवी तत्वों ने फैक्ट्रियों के अन्दर घुस कर तोड़फोड़ की, जम कर उत्पात मचाया। मौके पर पुलिस मौजूद थी लेकिन उपद्रवियों के सामने से पुलिस चुपचाप खिसक गई। एकाएक हाथ में लाठी-सरिये लिये लोग अन्दर घुस गये और बोले कि सोमवार तक फैक्ट्री नहीं चलानी। मजदूरों की तालमेल कमेटी ने किसी भी यूनियन से, किसी भी श्रमिक संगठन से सम्पर्क नहीं किया। किसी भी यूनियन ने फैक्ट्रियाँ बन्द करने की बात नहीं की है। ऐसे माहौल में फैक्ट्री चलाना मुश्किल है।

इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी के बयान पर पुलिस ने 10 अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया। और, पुलिस 18 मजदूरों को गिरफ्तार कर चुकी है।

✶प्लॉट 332-33-34 सैक्टर-24, फरीदाबाद स्थित इण्डो ऑटोटेक कम्पनी के 1 प्लान्ट में मैनेजमेन्ट शिफ्टों के समय बदलती रहती है। इस समय सुबह 8 से रात 8 बजे तक रहती शिफ्ट की बात है। शुक्रवार, 31 जनवरी को मजदूर साँय 5 बजे फैक्ट्री से बाहर निकलने लगे तो कम्पनी ने गेट बन्द कर दिये और पुलिस बुला ली। चार जिप्सी और एक बस में पुलिस फैक्ट्री गेट पर पहुँच गई। निकास स्थानों पर पुलिस ही पुलिस। इस पर मजदूरों का रुख था : नहीं निकलने देते तो मत निकलने दो, काम हम भी नहीं करेंगे। तीन घण्टे मजदूर फैक्ट्री में ऊपर-नीचे, इधर-उधर घूमते रहे और मशीनें बन्द रही।

✶सरकारी क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) में ठेकेदारों के जरिये रखे और दस वर्ष से ज्यादा समय से हिसार क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों ने सूचना के अधिकार कानून (आर टी आई एक्ट) का इस्तेमाल कर बी एस एन एल, ई एस आई कॉरपोरेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) से जानकारी एकत्र की। इस सामग्री का प्रयोग कर इन मजदूरों ने बी एस एन एल अधिकारियों और ठेकेदार कम्पनी द्वारा धोखाधड़ी द्वारा मिल कर मजदूरों के पैसे हड़पने के दस्तावेजी सबूत तरतीबवार तैयार किये। फिर इन मजदूरों ने डी सी हिसार को यह सामग्री दे कर कानून अनुसार कार्रवाई के लिये पत्र दिया। डी सी ने श्रम विभाग को जाँच के लिये पत्र लिखा। श्रम एवं समझौता अधिकारी हिसार ने बी एस एन एल अधिकारियों, ठेकेदार कम्पनी और मजदूरों को बुला कर जाँच की। श्रम अधिकारी ने इधर 23.1.2014 को डी सी हिसार को भेजे पत्र में मजदूरों के दावे को सही करार दिया है। बी एस एन एल अधिकारियों ने टालमटोल कर जिन दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया उन्हें पेश करने को भी कहा है। ....

✶अपने अनुभव व विचार मजदूर समाचार में छपवा कर चर्चाओं को और बढाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते। ✶बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दें। ✶महीने में एक बार छापते हैं, 12,000 प्रतियाँ निशुल्क बाँटने का प्रयास करते हैं। चर्चाओं के लिए समय निकालें।

निमन्त्रण

फरवरी में 23 तारीख वाले रविवार को मिलेंगे। सुबह 10 से देर साँय तक अपनी सुविधा अनुसार आप आ सकते हैं। फरीदाबाद में बाटा चौक से थर्मल पावर हाउस होते हुए रास्ता है। ऑटोपिन झुग्गियाँ पाँच-सात मिनट की पैदल दूरी पर हैं।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए रौनिजा प्रिन्टर्स फरीदाबाद से मुद्रित किया। **RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73/12-14**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी—551 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।